P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-10* June- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

डॉ. भीमराव अम्बेडकरः– एक महान् अर्थशास्त्री
Dr. Bhimrao Ambedkar - A Great Economist

Paper Submission: 05/06/2021, Date of Acceptance: 12/06/2021, Date of Publication: 24/06/2021

अनुकृति परसोया
छात्रा
अर्थशास्त्र विभाग,
राज. कला कन्या
महाविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

प्रेमलता परसोया
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
विराटनगर, जयपुर,
राजस्थान, भारत

सारांश

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक की समाप्ति के आसपास भारत में एक साथ, दो तरह के आन्दोलन गति प्राप्त कर रहे थे, इनमें एक भारतीय स्वतन्त्रता का संघर्ष था, जिसमें अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आन्दोलन किया जा रहा था। दूसरी तरफ भारत के ही अस्पृश्य समाज द्वारा सवर्ण हिन्दू वर्गो के विरूद्ध, छुआछूत को खत्म करने तथा अस्पृश्यों को सवर्णों की गुलामी से मुक्त करवाकर उनके हितों की रक्षा के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा था। अस्पृश्यों के आन्दोलन को डॉ. भीमराव अम्बेडकर नेतृत्व प्रदान कर रहे थे जिन्होनें न्यूयार्क की कोलम्बिया विश्वविद्यालय से एम. ए., एम. एस. सी., पी.एच.डी., डी. एस. डी., बार–एट–लॉ ..... की डिग्रियाँ प्राप्त की थी। तत्कालीन समय में अस्पृश्यों को छूने मात्र से अन्य वर्ग अपने आप को अपवित्र मानते थे तथा अछूतों को स्कूल, तालाब, कुएँ, अस्पताल ..... आदि सार्वजनिक उपयोग की संस्थाओं का लाभ नहीं उठाने दिया जाता था। डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यों को समानता का दर्जा दिलवाने तथा आर्थिक अवसरों की समानता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार से भी अनुरोध करके लन्दन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी शामिल होने गये। भारत की आजादी मिलने के बाद देश में नया संविधान निर्मित कर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता स्थापित की। परन्तु किन्ही कारणों से उनका आर्थिक क्षेत्र का योगदान अधिक महत्व या फोकस प्राप्त नहीं कर सका।

Around the end of the second decade of the twentieth century, two types of movements were gaining momentum simultaneously in India, one of which was the struggle for Indian independence, in which the movement was being conducted under the leadership of Mahatma Gandhi to expel the British from India. On the other hand, a movement was being run by the untouchable society of India against the upper caste Hindu classes, to end untouchability and to protect the interests of the untouchables by getting them free from the slavery of the upper castes. The movement of the untouchables by Dr. Bhimrao Ambedkar, who received his MA, MS from Columbia University in New York. C., Ph.D., D.S. D., Bar-et-Law degrees. In those days, by merely touching the untouchables, other classes considered themselves impure and the untouchables were not allowed to take advantage of public utilities like schools, ponds, wells, hospitals, etc. Dr. Ambedkar also went to attend the three Round Table Conferences organized in London by requesting the British Government to get equal status for the untouchables and to get equality of economic opportunities. After the independence of India, by creating a new constitution in the country, political, economic and social equality was established. But for some reason his contribution to the economic sector could not get much importance or focus.

मुख्य शब्द : अस्पृश्य, समानता, अधिकार, गरिमापूर्ण, अध्ययन, विश्वविद्यालय, सम्मेलन, अर्थव्यवस्था, आजीविका, मुद्रा, महंगाई, साम्राज्यवाद, नेतृत्व, आन्दोलन, विशेषाधिकार, संविधान, प्रतिभा, विद्वता, लोककल्याण, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, न्याय, समाजवाद।

Untouchable, Equality, Right, Dignified, Study, University, Conference, Economy, Livelihood, Currency, Inflation, Imperialism, Leadership, Movement, Privilege, Constitution, Talent, Scholarly, Public welfare, Self-respect, Self-respect, Justice, Socialism.

प्रस्तावना

भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद्, समाजशास्त्री, वक्ता, प्रवक्ता, लेखक, उच्च कोटि के महामानव थे जिन्होनें भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपनी महान्तम भूमिका निभाकर, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाकर दिया। मानवता से सरोबार वो, वंचितों व शोषितों का मसीहा थे जिन्होनें भारतीय समाज में स्थायी स्वरूप ले चुकी जातिगत विषमता को कनून की धार से खत्म किया। डॉ. अम्बेडकर, जिन्होनें यूरोप अमेरिका में अध्ययन किया था, को भारत में भी लोकतन्त्र मात्र एक शासन प्रणाली के रूप में नहीं स्थापित किया अपितु एक जीवन दर्शन के रूप में इसकी नींव स्थापित की तथा देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को दिलाकर गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण जीवन उपलब्ध करवाया। 'एक व्यक्ति – एक वोट' द्वारा भारतीय समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाकर भारत को विश्वशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनका आर्थिक सामर्थ्य आम जन के मानस से या तो ओझल हो गया है या समझ से दूर रह गया है इसी का अध्ययन इस शोध पत्र में किया जायेगा।

समस्या का चयन

आज डॉ. भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता या अछूतों/दलितों का नेता के रूप में स्मरण किया जाता है जबकि उन्होनें लन्दन विश्वविद्यालय (लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स) में अध्ययन करते समय ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करके भारत की विपन्नता का प्रमुख कारण बताया। भले ही वो उस समय सामाजिक समानता के संघर्ष में अधिक डूबे हुए थे परन्तु भारत की अर्थव्यवस्था के पतन की ओर अग्रसर होने से वो बहुत चिन्तित थे और इसके लिए उन्होनें ब्रिटिश सरकार को भी कोसा। अपनी थीसिस 'रूपये की समस्या' में उन्होनें पौण्ड (ब्रिटिश मुद्रा) द्वारा किस प्रकार रूपये (भारतीय मुद्रा) को गिराया है का गहन विश्लेषण किया है। डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक क्षेत्र में दिये गये योगदान का अध्ययन इस शोध पत्र में करे का प्रयास किया जायेगा।

अध्ययन का उद्देश्य

आज भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 3–4 वर्षो में लगातार पतन की ओर अग्रसर हो रही है तथा गरीबी और बेरोजगारी ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया है। भीमराव अम्बेडकर ने एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक स्वरूप की सुदृढ़ता को अपरिहार्य माना तथा इसके लिए वांछित समाधान भी प्रस्तुत किये, इनका अध्ययन इस शोध पत्र में करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

साहित्यावलोकन

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (हिन्दी अनुवादक–रमेश कपूर)	–	रूपये की समस्या उद्भव और समाधान, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम सम्यक संस्करण : 2018
क्रिस्तोफ जाफलो	–	भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी राजकमल पेपरबैक्स, नई दिल्ली, तीसरा संस्करणः 2020
सं. दिनकर कुमार	–	मैं आंबेडकर बोल रहा हूँ प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, 2020
वालेरियन रोडरिग्स (सम्पादन)	–	द एसेन्सीयल राइटिंग्स ऑफ बी. आर. अम्बेडकर ऑक्सफोर्ड इण्डिया, पेपरबेक्स
गणेश मन्त्री	–	गाँधी और अम्बेडकर, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
डॉ. एम.एल. परिहार	–	बाबा साहेब अम्बेडकर, लाइफ एण्ड मिशन बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर
नानक चन्द रत्तू	–	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण सन्देश एवं विद्वतापूर्ण कथन, डी.के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट, मुम्बई
रत्न कुमार साभंरिया	–	डॉ. अम्बेडकरः एक प्रेरक प्रसंग बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर
डॉ. धर्मवीर चन्देल	–	मानवाधिकार में डॉ. अम्बेडकर का योगदान राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
गेल ओमवेट	–	अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर पेंगुइन रैण्डम हाऊस इण्डिया

मानव सभ्यता के इतिहास में मानवता का उद्धार करने के लिए विश्व स्तर पर अनेक महापुरूषों ने अपने जीवन दर्शन तथा व्यक्तित्व एवं कृतित्व द्वारा मानवता के संरक्षण एवं प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की पुण्य भूमि पर भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर ऐसे ही महापुरूष हुए है जिन्होनें बिना किसी रक्तपात के वैचारिक चिन्तन और अपनी ज्ञान साधना के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को अभि शापित जीवन से मुक्त करवाकर सामाजिक–आर्थिक न्याय की स्थापना करके भारत को व्यावहारिक स्वरूप में एक सुदृढ़ स्थायी लोकतन्त्र के रूप में स्थापित किया और वो समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वक्ता, लेखक और भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते है।

डॉ. अम्बेडकर को अपने शुरूआती जीवन में समाज में सामाजिक व राजनीतिक समानता स्थापित करने के संघर्ष में जुटना पड़ा, इस लिए आर्थिक क्षेत्र में उनके महान् योगदान को आम भारतीय कभी जान ही नहीं

पाया। यद्यपि डॉ. अम्बेडकर ने तो जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी वर्गो, हितों के संरक्षण तथा उनके अधिकार और स्वतन्त्रता दिलवाने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनकी शिक्षा और डिग्रियों में अर्थशास्त्र का वर्चस्व ही रहा है, हाँ उनकी डिग्रियों और भाषाओं की जानकारी का कोई सानी नहीं है।

समाज में चारों तरफ अन्धकारपूर्ण वातावरण मे एक अछूत समाज (महार जाति) में जन्म लेने के कारण जातिगत तिरस्कार तथा अपमान की नेहमतें तो स्वाभाविक रूप से उनकी झोली में 14 अप्रेल 1891 को ही आ चुकी थी। यद्यपि पिता रामजीराव सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर रहे थे इसलिए घर का माहौल आधुनिकता की तर्कपूर्ण सोच से बना हुआ था तथा अनुशासन उनके घर में दिनचर्या में आदत के रूप में आ चुका थ।

फिर शुरू हुआ स्कूल में, प्रवेश की पाबन्दियों के बावजूद पिता के अकथनीय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तों के साथ दाखिला और फिर जातिगत अपमान, कड़वे शब्द भी उनकी दिनचर्या में इस तरह से शामिल हो गये जैसे हमारी दिनचर्या में चाय और भोजन शामिल हो। परन्तु बालपने की उन कोमल भावनाओं पर सशक्त जातिगत अत्याचारों की चोट भी शिक्षा के मार्ग से उन्हें वंचित नहीं कर पाई और शिक्षा की शुरूआत से ही वो समझ गये कि ये ही वो शस्त्र हो सकता है जो कि हिन्दू समाज की जड़त्व रूपी जातिगत भ्रान्तियों को तोड़ सकता है। उनका जब–जब भी अपमान होता उनके मन में एक गहरा भाव उत्पन्न कर जाता और वे अपने अछूत समाज की अभिशप्त जिन्दगी की मुक्ति के लिए अन्तर्मन में एक दृढ़ निश्चय करते रहते।

देश–विदेश में शिक्षा और अर्थशास्त्र पर बल

यद्यपि जातिगत–रूढ़िगत समस्याओं के बावजूद भीमराव अम्बेडकर के जीवन में नैतिक और आर्थिक सहयोग देने वाले सहृदय व्यक्तियों का अस्तित्व भी बना रहा और यही वजह रही कि वो अपने दृढ़ निश्चय को अपनी जिन्दगी में ही क्रियान्विति के स्तर पर ले जा पाये और समाज से छुआछूत जैसी घातक बीमारी का उन्मूलन भी कर पाये। इनमें अम्बेडकर गुरूजी, बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़, केलुस्कर जी, नवल भटेना आदि का नाम स्वतः स्मरण में आ जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने देश–विदेश से शिक्षा की निम्नानुसार उच्च डिग्रियाँ लेने वाले पहले भारतीय बने–

1. प्रारम्भिक व हाईस्कूल शिक्षा – सतारा व एलफिंस्टन स्कूल बम्बई
2. बेचलर ऑफ आर्ट्स – एलफिंस्टन कॉलेज, बम्बई विश्व विद्यालय
3. मास्टर ऑफ आर्ट्स – कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क
4. विद्या वाचस्पति – कोलम्बिया विश्वविद्यालय
5. डी. फिल. व डी. एस. सी. – लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, लन्दन विश्वविद्यालय
6. बार–एट–लॉ – ग्रेज इन, लन्दन
7. एल.एल.डी. – कोलम्बिया विश्वविद्यालय
8. डी. लिट – उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

डॉ. अम्बेडकर ने तत्कालीन विषमतामूलक परिस्थितियों तथा बिना सुख–सुविधाओं के इतनी अधिक डिग्रियाँ अपनी योग्यता द्वारा हांसिल की, ये उनकी महानता का प्रमाण ही है।

डॉ. अम्बेडकर ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से सबसे ज्यादा अध्ययन किया है और इसीलिए उक्त विश्वविद्यालय ने उन्हें 250 वर्ष के सर्वे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी की उपमा से नवाजा है।

उनके द्वारा कोलम्बिया विश्वविद्यालय से किए गए कोर्स :–

क्र.सं.	अध्ययन कोर्स	संख्या
1	अर्थशास्त्र	29
2	इतिहास	11
3	समाजशास्त्र	6
4	दर्शनशास्त्र	5
5	मानवशास्त्र	4
6	राजनीति	3
7	फ्रेंच	1
8	जर्मन	1

(स्रोत : इन्टरनेट व विभिन्न पुस्तकों से)

उक्त तालिका के अध्ययन से ही पता चलता है कि अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था और इसमें 29 कोर्सेस किए थे। डॉ. अम्बेडकर का यह भी सौभाग्य रहा कि विश्व के दिग्गज अर्थशास्त्रियों जैसे प्रो. सेलिगमेन, प्रो. एडविन कैनन आदि से अध्यापन का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त जॉन ड्यूई जैसे दार्शनिक तथा गोल्डनवाइजर जैसे मानवशास्त्री का सानिध्य व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आर्थिक मुद्दों का देश व समाज में क्या महत्व है ये डॉ. अम्बेडकर जानते थे इसलिए उन्होनें कहा था – ''इतिहास हमें बताता है कि जब भी आर्थिक और नैतिक मुद्दो के बीच टकराव होता है तो जीत हमेशा आर्थिक मुद्दो की होती है। निहित स्वार्थ कभी भी अपने हितों को नहीं त्यागते जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर न कर दिया जाए।[1]

जीवन व देश के लिये 'अर्थ' का कितना महत्व हो सकता है, ये डॉ. अम्बेडकर को नित्य–प्रतिदिन की आर्थिक तंगी से समझ आ चुका था। उन्हें डॉक्टर ऑफ साइन्स (डी.एस.सी.) की डिग्री उनके थीसिस 'रूपये की समस्या' पर ही अवार्ड हुई थी।

इस ग्रन्थ की भूमिका उनके शिक्षक प्रो. एडविन कैनन द्वारा लिखी गई। हालांकि प्रो. एडविन डॉ. अम्बेडकर द्वारा की गई ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना से सहमत नहीं थे लेकिन इसके बावजूद उन्होनें अम्बेडकर

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-10* June- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

की बुद्धिमता से लिखे गये ग्रन्थ की बहुत तारीफ की। यहीं नहीं दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की। इसमें अम्बेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रूपये का पौण्ड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफी नुकसान पहुँचाया है।[2] यद्यपि बाबा साहेब आर्थिक विषय पर आगे अपना शोध जारी नहीं रख पाये क्योंकि यहाँ अस्पृश्यों को उनकी दासता से आजादी दिलाना उनकी प्राथमिकता थी परन्तु आर्थिक विषय का उनके व्यक्तित्व व ज्ञान पिपासा में सदैव महत्वपूर्ण भाग रहा। उनके सामाजिक मुद्दों के हल के लिए वो अर्थशास्त्र के आधार को रखते थे। वो अपने अछूत समाज को भी आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनने की हिदायत दिया करते थे। क्योंकि अस्पृश्यों की आर्थिक जरूरतों को पूरी करने के बदले में ही सवर्ण हिन्दू उन्हें दास बनाकर रखते थे तथा अछूतों द्वारा यदि कभी किसी घिनौने कृत्य के आदेश का उल्लघंन करना चाहा तो सवर्ण हिन्दू समुदाय सामूहिक रूप से उनकी रोजी–रोटी बन्द करने की धमकी देता था।

वो सदैव कहा करते थे कि आर्थिक उत्थान के बिना सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान भी असंभव है। उनकी यह बात भी बड़ी खास थी कि जिस समस्या पर विचार प्रारम्भ करते थे उसके प्रासंगिक तथा व्यावहारिक समाधान भी सुझाते थे। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर,भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ, भूमिहीन मजदूरों तथा कृषकों की समस्या .... आदि विषयों पर गहन चिन्तन करके, उनके समाधानों का मार्ग भी बतलाया। बाबा साहेब की आर्थिक प्रतिभा व विद्वता के लिए ही, डॉ. अमर्त्य सेन जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने भी प्रशंसा की व उन्हें आर्थिक मसलों पर पिता तुल्य स्वीकार किया। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि अमीरी और गरीबी के बीच गहरी खाई का निर्माण पूँजीवादी व्यवस्था की देन है ये सामाजिक असमानता को उत्पन्न करती है।

ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों में कमियाँ उजागर की

1926 में अम्बेडकर ने भी मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी रॉयल कमीशन के समक्ष साक्ष्य दिया। उन्होनें रूपये–पाउण्ड विनिमय दर के बारे में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इस पुस्तिका में भारत के विभिन्न वर्गो पर पड़ने वाले मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव का विश्लेषण दिया गया था। अम्बेडकर ने तुलनात्मक रूप से रूपये के कम मूल्य के बारे में दलील दी। ब्रिटिश सरकार ने भी अम्बेडकर के आर्थिक चिन्तन की क्षमताओं को चहचानना शुरू कर दिया।[3]

डॉ. अम्बेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था को न्यायसंगत स्वरूप में स्थापित करना चाहते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर समान अवसर उपलब्ध हो। किसी के हित के लिए 'बहुतों के हितों के त्याग' की अवधारणा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये टर्म 'विशेषाधिकार' के सिद्धान्त पर अवलम्बित है जो कि समाज के विखण्डन का आधार है।

किसी भी शोध की सार्थकता तभी प्रकट होती है जब उसे व्यवहार में क्रियान्वित किया जावे और बाबा साहेब ने अपनी शोध के निष्कर्षों को व्यावहारिक दृष्टि से समाज पर लागू किया। जो राष्ट्र नागरिकों को गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से निजात नहीं दिला सके तो वह पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। चूँकि डॉ. अम्बेडकर पूँजीवाद को भारत जैसे देश के लिए कतई उचित नहीं मानते थे क्योंकि यहाँ सामाजिक–राजनीतिक आधार पर व्यक्तियों के बीच इतने गहरे अन्तराल है कि यहाँ समानता शब्द का कोई महत्व ही नहीं समझ सकता है। एक ओर पूर्ण शानौ–शौकत युक्त जीवन जीने वाला, अल्प संख्या वाला वर्ग, दूसरी तरफ दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी महरूम रहने वाला वर्ग .... , ये पूँजीवाद के परिणाम है। इसलिए उन्होनें उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य बताया था।

समाजवाद पर बल

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक संवैधानिक सुधार तथा आर्थिक समस्याएँ में राज्य पर यह दायित्व डाला है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करे कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिन्दु हासिल हो जाए और निजी उद्यम के लिए एक भी मार्ग बन्द न हो और सम्पदा के समान वितरण के लिए भी उपबन्ध किया जाये। इसमें वर्णित योजना के अनुसार कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व प्रस्तावित है, जहाँ सामूहिक पद्धति से खेतीबारी की जाए तथा उद्योग के क्षेत्र में राजकीय समाजवाद का रूपान्तरित रूप भी प्रस्तावित है। इसमें कृषि एवं उद्योग के लिए आवश्यक पूँजी सुलभ कराने की बाध्यता राज्य के कन्धों पर स्पष्ट रूप से डाली गई है। राज्य द्वारा पूँजी उपलब्ध कराये बिना कृषि या उद्योग से बेहतर परिणाम नहीं लिए जा सकते।[4] समाजवाद के पक्ष में डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा, भारत का तेजी से औद्योगीकरण करने के लिए राजकीय समाजवाद अनिवार्य है। निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकता और यदि कर सकता है तो वह सम्पदा की विषमताओं को जन्म देगा, जो निजी पूँजीवाद ने यूरोप में पैदा की है और जो भारतीयों के लिए एक चेतावनी होगी। चकबन्दी और काश्तकारी विधान व्यर्थ से भी बदत्तर है। उनसे कृषि क्षेत्र समृद्ध नहीं हो सकता। न तो चकबन्दी और न ही काश्तकारी विधान छः करोड़ अस्पृश्यों के लिए सहायक हो सकते है, जो भूमिहीन मजदूर है। प्रस्ताव में वर्णित विधि से स्थापित सामूहिक फार्म ही उनके लिए सहायक हो सकते है।[5]

महात्मा गाँधी से आर्थिक मुद्दों पर मतभेद

महात्मा गाँधी और डॉ. अम्बेडकर के बीच एक बड़ा अन्तर आर्थिक दृष्टिकोण में भी पाया जाता है, गाँधी कहते है कि गाँवों से पलायन नहीं होना चाहिए बल्कि गाँवों में रहकर पैतृक व्यवसायों को अपनाकर, आत्मनिर्भर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। गाँधी बड़े उद्योगों अर्थात् भारी मशीनरी पर आधारित औद्योगीकरण के खिलाफ थे क्योंकि उद्योगों में मशीनरी के अत्यधिक प्रयोग का परिणाम बेराजगारी के रूप में निकलकर आता है। मशीनों का अत्यधिक प्रयोग होने पर मानवीय श्रम की बचत होने लगती है जिससे कारखानों से अतिरिक्त मजदूरों की छंटनी कर दी जाती है तथा इससे गरीबी भी बढ़ती है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्र में महारत हासिल डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि गाँव अब केवल सामाजिक रूढ़िवादिता तथा जातीय भेदभाव को बचाये रखने के अड्डे बन गये है इसलिए रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर उन्मुख होना चाहिए। बाबा साहेब कहते थे कि देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण की प्रमुखतः आवश्कता है, क्योंकि ये बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान करते है। हाँ, लेकिन औद्योगीकरण सरकार अथवा राज्य के संरक्षण तथा निगरानी में होना चाहिए अन्यथा निजी व्यक्तियों के निर्देशन में होगा तो वह आर्थिक असमानता को बढ़ाने में सहायक होगा। निजी क्षेत्र केवल 'मांग और पूर्ति' अर्थात् लाभ के सिद्धान्त के आधार पर चलता है जबकि राज्य के संरक्षण में औद्योगीकरण होने पर सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का ख्याल रखा जाता है।

हालांकि डॉ. अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, उद्योगो के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने का आधार है तथा देश की बड़ी सी जनसंख्या को भोजन व रोजगार भी उपलब्ध करवाती है। इसके लिए भूमि का असमान वितरण सबसे पहले खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पास पूरा–पूरा गाँव जहाँ तक बसा होता है, उतनी जमीन होती है तथा दूसरी और बहुसंख्यक लोग भूमिहीन होते है जो भूमिपत्तियों के यहाँ अपना श्रम बेचकर अपनी आजीविका का अर्जन करते है।

20वीं शताब्दी का तीसरा दशक, विश्व स्तर पर आर्थिक उथल–पुथल के लिए जाना जाता है, इसमें पूरा विश्व ही लगभग आर्थिक मन्दी की चपेट में आ गया था। गरीबी तथा बेरोजगारी अपने आकार में वृद्धि करती जा रही थी, ऐसे में अनेक उपनिवेशों (एशिया) के स्वामी ब्रिटेन को भी उपनिवेशों की जनता की स्थानीय समस्याओं के समाधान में दिक्कतें आ रही थी। इन उपनिवेशों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के संघर्ष जोर पकड़ते जा रहे थे और आर्थिक मन्दी की समस्याओं से घिरने के कारण ब्रिटिश सरकार की अपने उपनिवेशों पर एक पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। इसलिए 1925 के अगस्त में ब्रिटिश सरकार ने 'रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेन्सी एंड फाइनेंस' का गठन किया जिसे भारत की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपनी थी।

ये महत्वपूर्ण तथ्य था कि डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक विद्वता के कारण 40 सदस्यों के दल में उन्हें भी शामिल किया गया। जब आयोग की बैठक प्रारम्भ हुई तो सभी सदस्यों के हाथ में डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक 'इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन ब्रिटिश इण्डिया' की प्रतियाँ हाथों में थी। ब्रिटिश सरकार ने तो अम्बेडकर की आर्थिक विद्वता को पहचान लिया था परन्तु उनके अपने ही देश में उनकी आर्थिक प्रतिभा नही समझी गई क्योंकि यहाँ पर तो प्रत्येक प्रतिभा और ज्ञान के पीछे उच्च जाति में जन्म लेने की शर्त अनिवार्य रूप से लगी हुई थी। डॉ. अम्बेडकर को विद्या वाचस्पति की डिग्री 'इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन ब्रिटिश इण्डिया' नामक शोध ग्रन्थ पर ही कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अवार्ड हुई थी।

आर्थिक विषयों की महत्ता लोकतन्त्र के लिए

डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण तथा समझ इतनी व्यापक थी कि कोई भी विषय उनके अध्ययन से अछूता नहीं रहा तथा समाज का कोई भी वर्ग उनकी सहृदयता से दूर नहीं रह पाया। जब सौभाग्यवश एवं उनकी प्रतिभा के कारण संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण का मौका मिला तो उन्होंने प्रत्येक वर्ग के हितों के संरक्षणार्थ विभिन्न प्रावधान रखे। इन सबके पीछे उनकी अर्थशास्त्र विषय पर दक्षता को ही समझा जाता है। नये संविधान में संसदीय लोकतन्त्र की वकालत करते हुए भी उसके सामाजिक तथा आर्थिक आधारों को विस्मृत नही दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने उक्त चित्र के अनुसार लोकतन्त्र को केवल शासन प्रणाली का आधार नहीं माना वरन् इसे एक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। राजनीतिक लोकतन्त्र इसके आर्थिक तथा सामाजिक स्वरूप के बिना केवल धनाढ्य उच्च वर्गों के बीच सत्ता का हस्तान्तरण मात्र रह जायेगा। लोकतन्त्र के सन्दर्भ में मानवीय अधिकारों की बात उनके आर्थिक दर्शन का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतन्त्र को भी समाजवादी आवरण में निहित करने का उनका मन्तव्य था प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण तथा प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है :–

राजनीतिक लोकतन्त्र चार आधार–स्तम्भों पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए जा सकते है :

1. व्यक्ति अपने आप में एक सिद्धि है।
2. व्यक्ति के कुछ अहरणीय अधिकार होते है, जिनकी गारण्टी उसे संविधान द्वारा दी जाए।
3. कोई विशेषाधिकार प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा न की जाए कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों में से किसी अधिकार का परित्याग करे।
4. राज्य दूसरों पर शासन करने के लिए गैर–सरकारी लोगों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित न करे।[6]

डॉ. अम्बेडकर ने एडम स्मिथ, रिकार्डो, पेरेटो, मिल को पढ़ा तो उन्होनें, कार्ल मार्क्स का भी गहन अध्ययन किया, परन्तु किसी की विचार को हूबहू अपने देश में स्वीकार या लागू करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि यहाँ की स्थानीय जरूरतों व परिस्थितियों के

अनुसार ही वो किसी योजना व विचार के क्रियान्वयन के पक्ष में रहते थे। उनका लक्ष्य भारत में एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना था जो सामाजिक – आर्थिक न्याय पर आधारित हो तथा सामाजिक परिवेश सौहार्दपूर्ण हो जिसमें किसी के पास विशेष होने से पूर्व न्यूनतम सभी के पास हो।

डॉ. अम्बेडकर में अपनी बात पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहने का गुण कूट–कूट कर भरा हुआ था, क्योंकि एक तो किसी भी विषय पर उनका गहराई से शोध किया हुआ होता था, दूसरी ओर उनका मन्तव्य एकदम पवित्र होता था। 1923 में 'रूपये की समस्या', इसका 'उद्‌भव और समाधान' विषय पर डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधि के लिए उन्होनें शोध ग्रन्थ लिखा था, लन्दन के ही विश्वविद्यालय में अध्ययन कर, वहीं की सरकार की भारत के प्रति अपनाई गई शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियों की आलोचना की। यह कृत्य कोई वीर–साहसी व्यक्ति ही कर सकता था जो कि डॉ. अम्बेडकर थे।

भारतीय मुद्रा में सुधार के सुझाव

1925 में 15 दिसम्बर को भारतीय मुद्रा और वित्त के सम्बन्ध में शाही आयोग के समक्ष दिये साक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा के सुधार की याजना में निम्न आवश्यकताओं पर बल दिया :–

1. टकसाल जिस प्रकार जनता के लिए बन्द है उन्हें उसी प्रकार से सरकार के लिए पूर्णतया बन्द करके रूपये का सिक्का बनाना बन्द कर दिया जाए।
2. स्वर्ण के एक उपयुक्त सिक्के का निर्माण करने के लिए सोने की टकसाल खोली जाए।
3. सोने के सिक्के तथा रूपये के बीच एक अनुपात निर्धारित कीजिए।
4. रूपया, स्वर्ण में परिवर्तनीय और सोना, रूपये में परिवर्तनीय नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों विधि द्वारा निर्धारित अनुपात पर असीमित वैध मुद्रा के रूप में वितरित व प्रचलित हो।[7]

उक्त आयोग द्वारा स्वर्णमान व मुद्रा परिवर्तनीयता व स्थिरता पर डॉ. अम्बेडकर से जानना चाहा तो उनका जवाब था – परिवर्तनीयता, मुद्रा की मात्रा को देश की आवश्यकताओं तक सीमित करने का एक साधन है, जिस परिवर्तनीयता का अभिप्राय केवल बाहरी कार्यो के लिए होता है, उसमें उस मुद्रा की मात्रा को सीमित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। फलतः ऐसी मुद्रा पर आप आन्तरिक मूल्यों को स्थिर नहीं रख सकते।[8]

बाबा साहेब द्वारा उक्त योजना व विचार उस समय दिये जब सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए अछूत समाज आन्दोलन कर रहा था और डॉ. अम्बेडकर उस संघर्ष के अगुवा थे इसलिए उनके आर्थिक ज्ञान को अछूतोद्धार के कार्यक्रम ने ढक दिया था। उन्होनें अपने समाज के लोगों से भी कहा था कि एक मानव–मानव के बीच साम्य की भावना तुम्हारा आत्मविश्वास संवर्द्धन करेगी मात्र इसलिए ही उन्होनें मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन शुरू किया है अन्यथा इन मन्दिरों में प्रवेश का अधिकार प्रात कर तुम्हारी, जीवन की अन्य समस्याएँ समाप्त नहीं होंगी। इससे तुम्हारी रोजी–रोटी की व्यवस्था नहीं हो सकती और न ही तुम्हारे आय के स्त्रोत ही बढ़ पायेंगे। उन्होनें समाज का आहवान करते हुए मार्क्स की उक्तियों की दलील देते हुए समझाया कि 'शिक्षा प्राप्त करो', 'अपने लोगों का संगठन बनाओं' तथा 'संगठित होकर संघर्ष करो'। तुम्हारे पास अभी खोने के लिए केवल तुम्हारी दासता है परन्तु संघर्ष से हासिल करने के लिए रोजगार, व्यवसाय तथा शासन सत्ता सभी पड़े है। इसलिए अपना आत्मविश्वास जगाओं और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम गुलामी की जिन्दगी में चैन की सांस कैसे ले सकते हो?

इण्डिपेण्डेंट लेबर पार्टी का गठन व मजदूरों, अछूतों में जागृति

डॉ. अम्बेडकर ने दलितों में जागरूकता के लिए ही 'मूकनायक' , 'बहिष्कृत भारत' और 'जनता' जैसे अखबारों का प्रकाशन शुरू किया था। उन्होनें अछूत समुदाय के लोगों को समझाया था कि तुम तुम्हारे परम्परावादी तथा अपमानजनक कार्यों को छोड़ दो तथा सामूहिक रूप से प्रयत्न कर छोटे–छोटे धन्धों की शुरूआत करो। इसके लिए तुम गाँवों का भी त्याग करो क्योंकि गाँव जातिगत संकीर्णता तथा अज्ञानता के अडड्‌े मात्र बनकर रह गये है। उन्होनें अपने लोगों को शिक्षा प्राप्त कर व्यवसाय की ओर उन्मुख होने के लिए भी प्रेरित किया क्योंकि नौकरी में व्यक्ति केवल अपने सीमित परिवार का ही पालन–पोषण करता है परन्तु व्यवसाय में वह अपने समुदाय के बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। उन्हें पूँजी पतियों के औद्योगीकरण में बिल्कुल विश्वास नहीं था क्योंकि पूँजिपतियों की दृष्टि में श्रमिक तथा श्रम के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता, जबकि श्रमिक एक व्यक्ति है तथा श्रम एक वस्तु हो सकता है। उनके लिए मजदूरों तथा श्रमिकों की महत्ता बहुत अधिक थी। इसलिए उन्होनें 'इण्डिपेंडेट लेबर पार्टी' (प्स्च्) का गठन किया था तथा इसके नामकरण के सन्दर्भ में कहा था कि 'लेबर' में डिप्रेस्ड क्लास स्वयंमेव ही समाहित है।

आई.एल.पी. के कार्यक्रम में अस्पृश्यों को वाकई सिर्फ मजदूरों के रूप में ही मान्यता दी गई थी। इस कार्यक्रम में आर्थिक प्रश्नों पर बहुत गहराई से विचार किया गया था और पूँजीवाद की आलोचना की गई थी। अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय मजदूर ब्राह्मणवाद और पूँजीवाद दोनों के शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है।[9]

पार्टी (आई.एल.पी.) ने औद्योगीकरण को राज्य की प्राथमिकताओं में जगह दी और आर्थिक विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य माना। अपने कार्यक्रम माध्यम से पार्टी ने औद्योगिक कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कई सुधारों के प्रस्ताव रखे तथा उनके लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के और अधिक अवसरों की माँग की।[10]

आज उन्हें एवं उनकी आर्थिक शोधों को याद किया जाता हैं क्योंकि वो देश के कृषि के विकास के लिए प्रांसगिक थी। डॉ. अम्बेडकर जैसे अर्थ विशेषज्ञ आज देश में होते तो किसानों को आत्महत्या जैसे घातक कदम नहीं उठाने पडते़। पूँजीप्रधान उत्पादन तथा मशीनीकरण पर आधारित कृषि नीति को उन्होनें छोटी जोतों के किसानों के लिए अनुपयोगी बताया। उन्होनें छोटी जोतों की समस्या के हल के लिए पूँजी और पूँजीगत माल में वृद्धि करना आवश्यक बताया, इसके लिए बचत के प्रोत्साहन पर फोकस किया और बचत के लिए अधिशेष उत्पादन को आवश्यक बताया।

संविधान निर्माण में आर्थिक मुद्दों का महत्व

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय आर्थिक हितों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रावधान रखे जैसे अनु. 16 द्वारा अवसरों की समानता दी गई तथा अवसर के आगे जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग .... आदि के भेदभाव का निषेध किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यक निर्धारित योग्यता के मापदण्ड के अलावा राजकीय सेवाओं में किसी को भी उक्त विभेदों के आधार पर अवसर से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 19 में जो छः प्रकार की स्वतंत्रताओं का विवेचन किया गया है, उनमें अपनी इच्छानुसार व्यवसाय या वृत्ति के अपनाने की स्वतन्त्रता दी गई है जबकि संविधान लागू होने से पूर्व व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय ही अपना सकता था। डॉ. अम्बेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा व योग्यतानुसार कार्य व्यवसाय के चयन की स्वतन्त्रता दी जो कि समाज में एक क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है।

संविधान में आर्थिक हितों से जुड़े प्रावधानों में अनुच्छेद 23 और 24 को लिया जा सकता है। अनु. 23 द्वारा बेगारी या बलात् श्रम को समाप्त किया गया अर्थात बिना प्रतिफल दिये किसी से कार्य नहीं करवाया जा सकता। अनु. 24 द्वारा 14 से कम उम्र के बालकों को खानों या कारखानों में अर्थात् खतरनाक कार्यो में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे कामों से बालकों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है वे कम उम्र में घातक बीमारियों के शिकार हो जाते है .... आदि कारणों से अनु. 24 में उक्त प्रावधान शामिल किया गया।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में मूल अधिकारों वाले भाग में राजनीतिक लोकतन्त्र व स्वतन्त्रता सम्बन्धी बातों को शामिल किया। दूसरी और राजनीतिक लोकतन्त्र की पूर्णता के लिए नीति–निर्देशक तत्वों वाले भाग में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित करने सम्बन्धी बातें शामिल की।

अनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनायेगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 39 (क) में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की बात निहित है।

अनुच्छेद 39 (ख) राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार से करे ताकि सार्वजनिक हित सर्वोत्तम साधन हो सके।

अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा ओर लोक सहायता पाने के अधिकार से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 42 में काम की मानवोचित व न्यायसंगत दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध है।

अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात शामिल है।

अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि की बात शामिल है।

अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन के संगठन को शामिल किया है। इसी तरह सार्वजनिक वित्त उसका मितव्ययितापूर्ण उपयोग आदि पर भी डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है 1994 में कराधान के मसविदे पर उन्होनें 'नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक' की नियुक्ति के प्रावधान की बात की ताकि सरकारें जनता से संचित धन का उपयोग नियमों के अधीन, बुद्धिमतापूर्वक मितव्ययितापूर्ण तरीकें से कर सकें। सरकार को धन उस उक्ति से खर्च करना चाहिए ताकि जनता का उस पर विश्वास बना रह सके। सरकारी धन को खर्च करते समय वित्तीय विवेक, सम्बन्धित मुद्दों की गहन समझ, प्रासंगिकता, व्यावहारिक अनुभव का आधार होना चाहिए न कि व्यक्तिगत हितों के अनुरूप।

देश में वित्त आयोग की स्थापना, केन्द्रीय बैंक की स्थापना डॉ. अम्बेडकर की प्रेरणा स्वरूप ही हो पाई तथा बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं व पानी व बिजली के लिए ग्रिड सिस्टम भी उन्हीं की देन है।

निष्कर्ष

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर अन्य सभी उपमाओं के साथ एक महान् अर्थशास्त्री भी थे जिन्होनें एक व्यक्ति से लेकर पूरे भारतवर्ष के आर्थिक हितों के संरक्षण को प्राथमिकता दी चूँकि वह दौर सामाजिक आधार पर भेदभाव एवं ऊँच–नीच की भावना से ओत–प्रोत था एवं डॉ. अम्बेडकर स्वयं एक अछूत समुदाय महार जाति में पैदा हुए थे। वो जन्मजात प्रतिभाओं के धनी थे और अपनी प्रारम्भिक शिक्षा की शुरूआत से लेकर आजाद भारत में कानून मन्त्री के पद पर पहुँचने तक उन्होनें भारतीय समाज की जातिगत व्यवस्था का त्रास झेलना पड़ा और इसीलिए उन्होनें बाल्यकाल से ही अपने अछूत समुदाय को छुआछूत जैसी घातक रूढ़ि से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। इसलिए यूरोप, अमेरिका से अध्ययनोपरान्त उन्होनें 'महाड़ तालाब सत्याग्रह' तथा 'कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह' जैसे कार्य में अपने को संलग्न किया और उनकी मेहनत, संकल्प व ज्ञान साधना का ही परिणाम है कि आजादी के बाद नवीन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को

दण्डनीय अपराध घोषित किया। दलित समाज को अन्य वर्गों की तरह जीवन जीने के सम्मानपूर्ण तरीके हासिल हुए, इसलिए वर्तमान में उन्हें सामाजिक सुधारक एवं संविधान निर्माता के रूप में ही जाना जाता है जबकि उनका एक आर्थिक दृष्टिकोण इन सबके पीछे ओझल हो गया।

वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्र डॉ. अम्बेडकर का प्रिय विषय था तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालय से उन्होनें अर्थशास्त्र, से सम्बन्धित 29 पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया था। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध लेख भी बहुत ज्ञानोपयोगी तथा सामाजिक हित से जुड़े हुए है। उन्होनें अपनी पी.एच.डी. व डी.एस.सी. की डिग्रीयों के शोध प्रबन्ध क्रमशः 'द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया' व 'द प्रॉब्लम ऑफ रूपी : इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशंस' अर्थशास्त्र के विषयों पर भी लिखे। उन्होनें भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा की गिरावट के लिए ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया। खास बात यह थी कि लन्दन विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् अर्थात् शोधरत् रहते हुए वहाँ की सरकार की मुद्रा नीति की पूर्ण आत्मविश्वास से आलोचना की और उनकी डी.एस.सी. के शोध ग्रन्थ 'रूपये की समस्या' की प्रस्तावना उनके शोध निदेशक प्रो. एडविन कैनन ने लिखी थी।

कृषि व्यवस्था के विकास पर भी उनका ध्यान था क्योंकि भारत की 70ः आबादी कृषि के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कार्यो में संलग्न थी। कृषि विकास हेतु औद्योगीकरण को अनिवार्य बताया परन्तु इसे राज्य के संरक्षण में रखने की बात भीमराव अम्बेडकर ने की। राज्य के संरक्षण के अभाव में पूँजीपतियों का उद्योगों पर आधिपत्य स्थापित हो जायेगा जो कि आर्थिक असमानता को जन्म देगा। इसमें श्रमिकों को एक वस्तु की तरह समझा जाता है जबकि राज्य के अधीन उद्योगों का विकास होगा तो वह सबकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता देगा। यही वजह थी डॉ. अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री ने डॉ. अम्बेडकर के लिए कहा था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है तथा इस क्षेत्र में वो मेरे पिता तुल्य है।

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे तथा लोकतन्त्र की सफलता क लिए भी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में समानता स्थापित करना चाहते थे। हालांकि अर्थशास्त्र विषय में उनकी प्रकृत्ति प्रदत्त रूचि व दक्षता थी परन्तु यहाँ के सामाजिक हालातों के कारण वो अर्थशास्त्र के विषय में अपना कैरियर नहीं बना पाये वरना विश्व के सर्वोच्च स्तर के अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती। उनकी खास बात ये थी कि उन्होनें अपने अर्थशास्त्र के शोधों द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों तथा मूल्यों का भारतीय समाज के सन्दर्भ में व्यावहारिक उपयोग किया।

उन्होनें ये अपनी गहन आर्थिक तथा वैचारिक संवेदना के कारण किया था। 'अर्थ' के मामले में उन्होनें सरकार के कत्तव्यों का भी उल्लेख किया तथा ये हिदायत भी दी कि सरकार को भी नियमों के अधीन रहकर, मितव्ययितापूर्वक खर्च करना चाहिए तथा सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य भी रखना चाहिए। आज के दौर में नोटबन्दी की गई, हालांकि इसे बिना योजना के लागू किया, अन्यथा यह कालाधन बाहर लाने का सटीक उपाय था। डॉ. अम्बेडकर ने 10–20 साल में मुद्रा के परिवर्तन की वकालत की थी। बाबा साहेब ने नीति–निर्देशक तत्वों में ऐसे आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना से सम्बन्धित प्रावधान रखे और राज्य से इनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की।

डॉ. अम्बेडकर ने आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए विशेषाधिकारों के अन्त की बात कही क्योंकि समाज में किसी एक नागरिक के साथ श्रेष्ठतम तभी किया जा सकता है जब किन्हीं लोगों के साथ निकृष्टतम किया जाये। इसीलिए उन्होनें भूमि सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि यह भूमि का अत्यधिक असमान वितरण पाया जाता है जिसके पीछे जाति–धर्म से युक्त संकीर्ण विचारधारा को समझा जा सकता है। एक बड़ा वर्ग भूमिहीन है जिसे अल्प परिश्रम में अपना श्रम भूमि स्वामी के पास बेचना पड़ता है।

डॉ. अम्बेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था को न्यायसंगतता का आधार प्रदान करना चाहते थे जिसमें 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की अवधारणा चरितार्थ हो और गरीबी, बेरोजगारी तथा महंगाई का खात्मा हो सके। उन्होनें इस बात का प्रतिपादन किया कि जिसके स्वामित्व में आर्थिक शक्ति है वही राजनीतिक सत्ता पर भी आधिपत्य स्थापित कर लेता है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग को शामिल करने का लक्ष्य भी आर्थिक व सामाजिक समानता ही लाना था डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय, समाजवाद जैसे शब्दों को प्रतिष्ठापित किया।

यदि गाँवों में रोजगार के साधन नहीं है तथा सृजन के भी आसार नहीं आ रहे है तो व्यवसाय व आजीविका के अर्जन हेतु शहरों की तरफ जाना चाहिए क्योंकि शहरों में जाति–धर्म की संकीर्ण दीवारें नहीं है। शहरों में किसी भी समुदाय का व्यक्ति, किसी भी किस्म का व्यवसाय अपना सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने वंचितो, शोषितों को अपने वक्तव्यों द्वारा झकझोरा, कहा कि तुम्हें गुलाम बनाया गया और तुमने स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारे शोषण का आधार है तुमने अपनी दासता की बेड़ियों को काटने के लिए कभी संघर्ष नहीं किया अन्यथा या तो तुम्हारी दासता का अन्त हो जाता या फिर तुम स्वयं खत्म हो जाते, और ये दोनों ही स्थितियाँ तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होती।

उन्होनें अछूत समाज को जागृत करने में यह भी कहा कि जिस काम की वजह से अन्य वर्ग के लोग तुमसे नफरत करते है, छुआछूत करते है, उस काम का त्याग कर दो। अपनी आजीविका के लिए अन्य विकल्प तलाश करो। अब तक तुमने अन्य विकल्पों के बारे में चिन्तन ही नहीं किया क्योंकि गुलामी की जिन्दगी में तुम्हें पेट भरने तक का सामान अन्य वर्गो/मालिकों ने दे दिया है। यदि तुमने स्वाभिमान के खातिर मरे जानवर उठाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया तो अवश्य ही समाज में तुम्हारे प्रति फैली घृणा की भावना खत्म हो जाएगी। मजबूरन तुम लोग अन्य आजीविका के विकल्पों की खोज में जुट जाओगे।

डॉ. अम्बेडकर ने मार्क्स का अध्ययन किया परन्तु वहाँ के और भारत के वर्गभेद में बड़ा अन्तर था क्योंकि यहाँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार पर वर्ग भेद है जबकि वहाँ आर्थिक आधार पर।

डॉ. अम्बेडकर ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को इसीलिए अपनाया ताकि राज्य द्वारा व्यक्ति के प्राकृतिक गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सके।

डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन कल्याणकारी दृष्टिकोण पर आधारित हैं जिसमें किसी वर्ग, जाति के लिए ही भलाई की बात नहीं है बल्कि समाज के सभी वंचितों, शोषितों, दलितों के लिए आर्थिक –सामाजिक समानता की स्थापना द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतानुसार अवसर प्रदान कर व्यक्तित्व विकास की स्वतन्त्रता प्रदान करने में है।

यदि उनकी ऊर्जा अछूतों के हक व अधिकार में नहीं लगी होती तो वे दुनिया के श्रेष्ठतम अर्थशास्त्रियों में शुमार रखते अब सरकारें व शोधार्थी उनके आर्थिक मूल्यों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण हेतु सुदृढ़ योजनाएँ बना रहे है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *व्हाट गाँधी एण्ड कांग्रेस हैव डन टू द अनाटचेबल्स*
2. *डॉ. एम.एल. परिहार–बाबा साहेब अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, 2017, पृष्ठ – 55*
3. *गेल ओमवेट–अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर*
4. *बाबा साहेब अम्बेडकर– संवैधानिक सुधार तथा आर्थिक समस्याएँ सम्पूर्ण वाड़्मय, खण्ड–2, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ – 193*
5. *फिर वही*
6. *फिर वही, पृष्ठ – 194*
7. *डॉ. बी.आर. अम्बेडकर – रूपये की समस्या, इसका उद्‌गम और समाधान। सम्पूर्ण वाड.मय खण्ड – 12, पृ. – 325*
8. *फिर वही, पृष्ठ –347*
9. *क्रिस्तोफ जाफलो – भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी जाति उनमूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण राजकमल पेपरबैक्स, नई दिल्ली, 2020, पृष्ठ – 94*
10. *फिर वही*
11. *डॉ. अम्बेडकर का सम्पूर्ण वाड.मय, खण्ड 1–21 पत्र पत्रिकाएँ।*